गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 323
दि. 27.03.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पश्चिम एशिया तनाव के बीच प्रधानमंत्री की आपात बैठक ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच भारत ने अपनी रणनीतिक सतर्कता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और ऊर्जा आपूर्ति पर मंडराते खतरे को देखते हुए Narendra Modi ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक बुलाई है। यह बैठक केवल एक औपचारिक समीक्षा नहीं, बल्कि संभावित आपात परिस्थितियों के लिए देश की सामूहिक तैयारी का आकलन भी मानी जा रही है। केंद्र सरकार का स्पष्ट संकेत है कि मौजूदा वैश्विक हालात का असर भारत पर सीमित रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल अत्यंत आवश्यक है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, खासकर Strait of Hormuz जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग पर। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति की धुरी माना जाता है, जहां से दुनिया का लगभग एक-तिहाई ऊर्जा संसाधन गुजरता है। हाल के घटनाक्रमों में ईरान द्वारा कई देशों के लिए इस मार्ग को सीमित करने की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। हालांकि भारत को फिलहाल इस प्रतिबंध से छूट मिली हुई है, लेकिन स्थिति कब बदल जाए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में राज्यों के साथ संभावित वैकल्पिक योजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति केवल अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में रसोई गैस की आपूर्ति में देरी

और कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम कमी की खबरों ने लोगों में चिंता पैदा की है। सरकार का मानना है कि यह स्थिति वास्तविक कमी से ज्यादा अफवाहों और घबराहट का परिणाम है। प्रधानमंत्री राज्यों को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे स्थानीय स्तर पर आपूर्ति और वितरण तंत्र को सुचारु बनाए रखें और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाएं।

केंद्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें से करीब 60 दिनों का स्टॉक वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, रिफाइंड उत्पाद और रणनीतिक भंडारण शामिल हैं। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले से तय है और देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इस स्थिति में घबराहट फैलाने वाली खबरों से बचने की अपील भी की गई है।

इस बीच, प्रधानमंत्री की बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और यदि स्थिति युद्ध में बदलती है, तो उनकी सुरक्षित वापसी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस संदर्भ में Operation Ganga और Vande Bharat Mission जैसे अभियानों का अनुभव काम आ सकता है। बैठक में राज्यों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने नागरिकों का अद्यतन डेटा तैयार रखें और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने की योजना बनाएं।

आर्थिक मोर्चे पर भी यह संकट कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर भारत में महंगाई पर पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों को आगाह करेंगे कि वे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं। जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी होगी, ताकि आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

सरकार ने यह भी बताया है कि कुछ स्थानों पर ईंधन की अधिक खरीद की घटनाएं सामने आई हैं, जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक संदेशों के कारण हुईं। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने स्थिति को संभालते हुए रातभर डिपो संचालित कर आपूर्ति को सामान्य बनाए रखा। पेट्रोल पंप संचालकों को राहत देने के लिए उनकी क्रेडिट सीमा एक दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर दी गई है, जिससे कार्यशील पूंजी की समस्या के कारण किसी भी स्थान पर आपूर्ति बाधित न हो।

एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी सरकार पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचाया गया है, जो कुल मांग का 60 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बड़ी मात्रा में एलपीजी की खेप भारत पहुंचने वाली है। देशभर में 22 आयात टर्मिनलों के माध्यम से इन आपूर्तियों को वितरित किया जाएगा। तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलिंडर की डिलीवरी कर रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।

सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को भी बढ़ावा दे रही है, जिसे सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब एलपीजी की जगह लेना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को मजबूत करना है। देश में सिटी गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे अब करोड़ों परिवारों को पीएनजी कनेक्शन मिल चुका है।

इन सभी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री की यह बैठक एक व्यापक रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह केवल वर्तमान संकट से निपटने की योजना नहीं, बल्कि भविष्य में इस तरह की वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी है। सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बावजूद देश के भीतर स्थिरता बनी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

ब्रिटेन में क्रिप्टो चंदे पर सख्त रोक: लोकतंत्र को विदेशी दखल से बचाने के लिए स्टार्मर सरकार का बड़ा फैसला

(जीएनएस)। लंदन। ब्रिटेन की राजनीति में फंडिंग के तौर-तरीकों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री Keir Starmer ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले क्रिप्टोकरेंसी चंदे पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल मुद्रा के जरिए होने वाला चंदा पारदर्शिता के दायरे से बाहर होता है और इसके माध्यम से विदेशी तथा अवैध धन आसानी से राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य चिंता यह है कि क्रिप्टोकरेंसी की प्रकृति गुमनाम (anonymous) होती है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पैसा किस स्रोत से आया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि विदेशी ताकतें या संदिग्ध संस्थाएं इस माध्यम से ब्रिटेन की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस संभावित खतरे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है।

इस फैसले के साथ ही सरकार ने राजनीतिक चंदे से जुड़े नियमों को और कड़ा करते हुए विदेश में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के योगदान पर भी सीमा तय कर दी है। अब कोई भी प्रवासी ब्रिटिश नागरिक एक

साल में अधिकतम एक लाख पाउंड तक ही राजनीतिक दलों को चंदा दे सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों की फंडिंग में संतुलन बना रहेगा और बाहरी प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा। हाल ही में जारी एक सरकारी रिपोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि क्रिप्टो डोनेशन का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है और यह एक "ब्लाइंड स्पॉट" की तरह काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल विदेशी फंडिंग के लिए किया जा सकता है। इस रिपोर्ट ने सरकार के फैसले को मजबूत आधार प्रदान किया।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। Reform UK पार्टी के नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी आज के दौर में एक वैध निवेश और लेन-देन का माध्यम बन चुकी है, और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करना तकनीकी प्रगति के खिलाफ है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार यह कदम उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए उठा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी को क्रिप्टो समर्थक वर्ग से अच्छा समर्थन मिल रहा है। विशेषज्ञों की राय इस मामले में बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सबसे अहम होती है। वहीं, कुछ विशेषज्ञ इसे अत्यधिक सख्त मानते हैं और कहते हैं कि सरकार को पूर्ण प्रतिबंध के बजाय एक नियामक ढांचा तैयार करना चाहिए था, जिससे क्रिप्टो डोनेशन को ट्रैक किया जा सके।

ब्रिटेन का यह कदम वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। कई देश अभी भी यह तय करने की प्रक्रिया में हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में किस तरह शामिल किया जाए। ऐसे में ब्रिटेन का यह निर्णय अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जहां चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

फिलहाल, स्टार्मर सरकार का संदेश साफ है—लोकतंत्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का ब्रिटेन की राजनीति और वहां की चुनावी व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, और क्या अन्य देश भी इसी दिशा में कदम उठाते हैं।

राहुल गांधी पर रिजिजू का हमला: "सलाहकार तय करते हैं उनके बयान, संसद में मर्यादा भी जरूरी"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के भीतर और बाहर सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार में मंत्री Kiren Rijiju ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं रखते, बल्कि उनके सलाहकार ही तय करते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संसद के भीतर राजनीतिक टकराव और बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है।

एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें राहुल गांधी से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच बैठक के दौरान संवाद होता है और विचारों का आदान-प्रदान भी होता है। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसद में औपचारिक रूप से बोलते समय एक निश्चित मर्यादा और परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है।

रिजिजू ने कहा कि जब कोई नेता संसद में बोलता है, तो वह केवल अपनी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता

है। ऐसे में उसके शब्दों और व्यवहार में गंभीरता और जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर वही बातें दोहराते हैं, जो उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्र सोच पर सवाल उठते हैं।

इस बयान के साथ ही रिजिजू ने राहुल गांधी के पहनावे को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसद जैसे गंभीर और प्रतिष्ठित मंच पर एक निश्चित ड्रेस कोड और शालीनता का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार, विपक्ष के नेता का पद केवल एक राजनीतिक भूमिका नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, जिसके अनुरूप आचरण और व्यक्तित्व दोनों का प्रदर्शन होना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष Somnath Chatterjee का जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि चटर्जी जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक उनका पहनावा सामान्य और अनौपचारिक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पीकर का पद संभाला, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और पहनावे में बदलाव किया, ताकि उस पद की गरिमा के अनुरूप दिखाई दें। इसी तरह, विपक्ष के नेता को भी अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

रिजिजू ने यह भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब उसने भी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हमेशा कुछ मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने संकेत दिया कि वर्तमान विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभाते समय इन सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक ओर जहां सत्तापक्ष विपक्ष पर लगातार हमलावर है, वहीं विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना कर रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं। राहुल गांधी की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज करती रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी अपने विचार खुद रखते हैं और वे जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं।

संसद के भीतर आचरण, भाषा और पहनावे को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर यह मुद्दा उठता रहा है कि जनप्रतिनिधियों को किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही मर्यादा और जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है।

फिलहाल, इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या यह मुद्दा संसद के भीतर भी गूंजता है।

दहेज हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश: "यह समाज के माथे पर कलंक, दोषियों को नहीं मिलेगी आसानी से राहत"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। Supreme Court of India ने दहेज हत्या को लेकर बेहद सख्त और संवेदनशील रुख अपनाते हुए इसे समाज के लिए "गहरा कलंक" करार दिया है। अदालत ने Patna High Court के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें एक आरोपी को जमानत दे दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि ऐसे जघन्य मामलों में अदालतों को जमानत देते समय अत्यधिक सतर्कता और न्यायिक विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

यह मामला न केवल एक महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, बल्कि यह उस व्यापक सामाजिक समस्या को भी उजागर करता है, जिसमें दहेज की कुरीति आज भी महिलाओं की जान ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, उसे जमानत देना उचित नहीं है, खासकर तब जब मामले में गंभीर साक्ष्य मौजूद हों।

अदालत ने पटना हाई कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि जमानत देते समय मामले के अहम पहलुओं, विशेषकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया में केवल औपचारिकताओं के आधार पर निर्णय लेना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बनकर सामने आई। आरोपी पक्ष ने दावा किया था कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर थी और उसने छठी मंजिल से कूदकर

आत्महत्या की थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। रिपोर्ट में महिला के शरीर पर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की गंभीर चोटों का उल्लेख था, जो यह संकेत देते हैं कि मौत से पहले उसके साथ हिंसा या संघर्ष हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को निर्णायक मानते हुए कहा कि ऐसे साक्ष्यों को नजरअंदाज करना न्याय के साथ समझौता है।

पीठ ने अपने फैसले में भावुक लेकिन सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज प्रथा आज भी भारतीय समाज में एक अभिशाप की तरह मौजूद है। लालच और सामाजिक दबाव के कारण न जाने कितनी महिलाओं को या तो प्रताड़ित किया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। कई मामलों में उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया कि महिला की शादी को महज डेढ़ साल ही हुए थे। भारतीय कानून के तहत, यदि शादी के सात साल के भीतर किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो उसे दहेज हत्या के रूप में देखा जाता है और मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। 1 सितंबर 2024 को हुई इस घटना में सिर की चोट और शॉक को मौत का कारण बताया गया था, जो इस मामले को और भी संदिग्ध बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में समाज को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। दहेज प्रथा केवल एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मानसिकता से जुड़ा मुद्दा है, जिसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी केवल कानून लागू करना ही नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा में संदेश देना भी है।

इसी कड़ी में कोर्ट ने आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट के जमानत आदेश को "अनुचित" और "कानून की नजर में गलत" ठहराते हुए रद्द कर दिया। यह फैसला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गंभीर अपराधों में केवल जेल में बिताए गए समय के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

यह निर्णय उन सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी जमानत पाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख न केवल न्यायिक प्रणाली की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समाज के लिए यह एक चेतावनी भी है कि दहेज जैसी कुप्रथा को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल एक कानूनी निर्णय है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है—कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अब सख्त और निर्णायक कार्रवाई का समय आ चुका है।

संपादकीय

गंगा फिर भी मैली

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की उस टिप्पणी को हमें एक गंभीर चेतावनी के रूप में लेना होगा, जिसमें कहा गया है कि प्रयागराज में गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वह आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है। एनजीटी का यह खुलासा इसलिये भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि कुछ ही माह बाद यानी जनवरी 2025 की पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अखाड़ों की सक्रियता बढ़ गई है। महाकुंभ को लेकर देश ही नहीं विदेश में भी खूब चर्चा होती है। यदि गंगाजल की गुणवत्ता को लेकर ऐसे ही सवाल उठते रहे तो देश-दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठेंगे कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई अनेक महत्वाकांक्षी व भारी-भरकम योजनाओं के बावजूद गंगा को साफ करने में हम सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। आखिर कौन है गंगा की यह हालत करने के गुनहगार? विडंबना देखिये कि तमाम सख्ती के बावजूद सैकड़ों खुले नाले गंगा में गंदा पानी गिरा रहे हैं। तमाम उद्योगों का अपशिष्ट पानी अनेक जगह गंगा में गिराया जा रहा है। वर्ष 2014 से गंगा की सफाई का महत्वाकांक्षी अभियान 'नमामि गंगे' शुरू किया गया था। बताया जाता है कि अब तक करीब चालीस हजार करोड़ की लागत से गंगा की सफाई की करीब साढ़े चार सौ से अधिक परियोजनाएं आरंभ भी की गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित शहरों में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने, उद्योगों द्वारा बहाये जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिये शोधन संयंत्र लगाने, गंगा तटों पर वृक्षारोपण, जैव विविधता को बचाने, गंगा घाटों की सफाई के लिये काफी काम तो हुआ लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। जो हमें बताता है कि जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और नागरिक अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं करेंगे, गंगा मैली ही रह जाएगी। सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं। दरअसल, लगातार बढ़ती जनसंख्या का दबाव और गंगा तट पर स्थित शहरों में योजनाबद्ध ढंग से जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था को अंजाम न दिये जाने से समस्या विकट हुई है। गंगा को साफ करने के लिये जरूरी है कि स्वच्छता अभियान एक निरंतर प्रक्रिया हो। एक बार की सफाई निष्प्रभावी हो जाएगी यदि हम प्रदूषण के कारकों को जड़ से समाप्त नहीं करते। इसके लिये गंगा के तट वाले राज्यों में पर्याप्त जलशोधन संयंत्र युद्ध स्तर पर लगाए जाने चाहिए। साथ ही गंगा सफाई अभियान की नियमित निगरानी होनी चाहिए। इसमें आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है यह खाद्य श्रृंखला को संबल देने वाली तथा हमारी आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ी है। गंगा में अघुलनशील कचरा व अन्य अपशिष्ट डालने से रोकने के लिये जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। यदि जागरूकता व प्रेरित करने से बात नहीं बनती तो इसके लिये जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए। साथ ही गंगा में जहरीला कचरा बहाने वाले उद्योगों पर भी आर्थिक दंड लगाना चाहिए। एक बात तो तय है कि सरकार के साथ जब समाज की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, गंगा का साफ होना असंभव जैसा हो जाएगा। गंगा सिर्फ बहती नदी नहीं है हमारे पुरखों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गंगा मुक्तिकामी भी है। जीवनदायिनी भी है। ऐसे में केंद्र सरकार की नमामि गंगा परियोजना में राज्यों की भागीदारी और जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। साथ ही स्वच्छता परियोजना की निरंतर निगरानी की जानी भी जरूरी है ताकि प्रयासों का स्थायी लाभ गंगा को स्वच्छ बनाने में मिल सके। सही मायनों में आज गंगा के उद्धार के लिये हर भारतीय को भगीरथ जैसा दायित्व निभाना होगा। तभी सदियों से अविरल बह रही जीवनदायी गंगा की प्रतिष्ठा भी फिर से स्थापित हो सकेगी। फिर एनजीटी को यह न कहना पड़ेगा कि फलां जगह का गंगाजल आचमन करने लायक नहीं रह गया है।

खंडित वैश्विक परिदृश्य में भारत की विशेष भूमिका

> मौजूदा खंडित वैश्विक व्यवस्था में भारत को अपनी जगह खोजने की जरूरत नहीं है, उसका खुद ही एक खास स्थान है। दरअसल, किसी एक पक्ष में होने की प्रवृत्ति से अधिक लाभकारी है,बतौर पुल कार्य करने की क्षमता। विशाल आकार इस देश को महाद्वीपीय आधार मजबूत करने के साथ-साथ समुद्र में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं शायद ही कभी एक ही पल में ढहती हैं; वे धीरे-धीरे कमज़ोर होती हैं। वर्ष 1945 के बाद जो ढांचा बनाया गया था, उसकी रूपरेखा में विनाशकारी अस्थिरता को रोकने के लिए शक्ति का निर्वाह नियमबद्ध ढंग से और प्रगति को अनुमानित प्रारूप से उकेरा गया था। दशकों तक, यह रूपरेखा कायम रही। तथापि, अपने शैशवकाल में भी, इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं की छाप साथ चलती रही। जिन देशों को इस व्यवस्था को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वे अक्सर समानांतर रणनीतिक एजेंडे अपनाते थे, जिन नियमों को खुद लिखा था उनकी परीक्षा लेते रहे। तत्पश्चात नियमों का चयनात्मक पालन सामान्य बन गया।

शीत युद्ध ने प्रतिद्वंद्विता के माध्यम से अनुशासन थोपे रखा; दुनिया बंटी हुई थी, लेकिन गुटों की अनुमानित स्थिति के कारण स्थिरता बनी रही। सोवियत संघ के पतन के बाद कुछ समय के लिए एक 'एक-ध्रुवीय' दौर आया, जिसमें वैश्वीकरण की गति तेज़ हुई और आपूर्ति श्रृंखलाएं महाद्वीपों तक फैलीं।

रणनीतिक तनाव के कारण : इस विस्तार के भीतर ही तनाव के बीज छिपे थे। परस्पर निर्भरता बढ़ी, लेकिन साथ ही विषमता भी। दक्षता की ललक, सहनशीलता से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ी। जिन नेटवर्कों ने समृद्धि लाने में मदद की, उन्होंने ही जोखिम भी पैदा कर दिया, जिसमें अपना फ़ायदा ज़बरन या महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को रोककर उठाया जा सकता था। आर्थिक एकीकरण, जिसे कभी एक स्व-स्थिरकारी माना जाता था, अब तेज़ी से प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आने लगा।

आज ढांचा खड़ा तो है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया। नियम का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन लागू चुनिंदा ढंग से ही होते हैं। हम जो देख रहे हैं, वह कोई अचानक आया पतन नहीं बल्कि जो

अनुशासन कभी व्यवस्था के दौरान कायम रहा, उसके प्रति सहमति को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। जैसे-जैसे पुरानी सहमति के स्तंभ कमज़ोर हो रहे हैं, दुनिया नए 'गुरुत्व केंद्र' की तलाश में है।

वह गुरुत्व केंद्र कौन प्रदान कर सकता है, यह मामूली सवाल नहीं। बदलती व्यवस्था का बहाव थामने में हरेक शक्ति एक समान समर्थ नहीं। इसके लिए भूगोल, इतिहास, सभ्यतागत स्मृति और संयम रखने के पिछले रिकार्ड को एक साथ मिलाने जरूरत है। इसे एक ऐसी रणनीतिक संस्कृति की भी जरूरत है, जिसकी नीयत किसी और पर अपना वर्चस्व स्थापित करना न हो; संवैधानिक त्वरित सोच की ज़रूरत है, जो एकरूपता थोपने के बजाय विविधता साथ लेकर चले। इसे एक ऐसे बहुलवादी लोकाचार पर आधारित होना चाहिए, जो मुक्त दुनिया के साथ जुड़ाव तो रखे, लेकिन खुद उसमें न डूबे। इन गुणों बगैर भटकाव स्वतः ठीक नहीं होता; बल्कि और गहरा होता जाता है और अक्सर उनको फ़ायदा देने लगता है, जिन्होंने नियम तो गढ़े, लेकिन उन पर अमल न करने के बहाने ढूंढ़ते हैं।

सभ्यता, पैमाना और दायित्व : भारत की सभ्यतागत स्मृति, उसकी भौगोलिक केंद्रीयता के साथ मिलकर, एक विशिष्ट रणनीतिक स्थिति का निर्माण करती है। यह अपने आप में एक महाद्वीप है, उत्तर में हिमालय का प्रश्रय है-ऐसा क्षेत्र जिसने लंबे समय ढाल और मार्ग की भूमिका निभाई। हिमालयी पर्वत श्रृंखला ने न केवल रक्षा की, बल्कि सदियों व्यापार का मार्ग बना रहा और आक्रमणों को भी सीमित किया; इस प्रक्रिया ने ऐसी सभ्यता को आकार दिया जो अपनी मूल पहचान खोए बिना बाहरी प्रभाव आत्मसात कर लेती है।

इसका प्रायद्वीपीय विस्तार साझे समुद्री क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो वैश्विक व्यापार की मुख्य धमनियों में इसकी अहम उपस्थिति यकीनी बनाता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडेब तक, वाणिज्य के प्रमुख समुद्री गलियारे भारत से सटकर निकलते हैं। ये सभी विशिष्टताएं भारत को अव्यवस्था का सामना करने की क्षमता के साथ स्थिर और संतुलित करने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं।

संतुलन बतौर सक्रिय रणनीति : विखंडित होती दुनिया में, संतुलन अब अपरोक्ष परिणाम नहीं रहा, एक सक्रिय रणनीति है। भारत का दृष्टिकोण, अपनी हस्ती कायम रखते हुए, वृहद जुड़ाव बनाना है, और अलग-थलग पड़े बिना स्वायत्तता बनाए रखनी है। ऐसे रुख को अक्सर रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, लेकिन इसका सार वाजिब संतुलन में है, प्रतिस्पर्धी ध्रुवों के बीच भी, संबंध बरकरार रखना और हितों को कमजोर किए बिना संवाद जारी रखने की क्षमता। यह मानकर कि अब गठबंधन अमूमन पूर्ण नहीं होता, परिस्थितिजन्य होता है। ऐसा संतुलन न तटस्थता है और न अनिर्णय। विखंडन के युग में, भावावेश में किसी एक पक्ष में होने की प्रवृत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, एक सेतु के रूप में कार्य करने की क्षमता।

बल का विश्वसनीय समायोजनीय संतुलन : संतुलन केवल संयम पर टिका नहीं रह सकता; जब यह खतरे में हो तब संयम तज कार्रवाई करने की विश्वसनीय क्षमता होनी चाहिए। दबाव डालने पर, भारत ने दृढ़ता व सही अनुपात में प्रतिक्रिया देने की इच्छाशक्ति दिखाई। बल प्रयोग संतुलन त्यागना नहीं; जब अन्य ढंग फेल हो जायें तब संतुलन बहाली का साधन है। मौजूदा परिदृश्य में, विश्वसनीयता गतिजता से अधिक व्यापक है। एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब युद्धक्षेत्र जागरूकता और निर्णय-क्षमता को आकार दे रहे हैं। विदेश से नियंत्रित तकनीकी पारिस्थितिकी पर निर्भरता नया जोखिम है, एक संभावना कि महत्वपूर्ण क्षणों में वह क्षमता ही गायब कर दी जाए। हालांकि, तकनीकी आत्मनिर्भरता संरक्षणवाद की ओर पीछे जाना नहीं; यह सुरक्षित संपर्क के लिए पूर्व-आवश्यकता है। यह एक संप्रभु डिजिटल कोर बनाने के बारे में है, जिसके जरिए प्रणालीगत निर्भरता बनाए बगैर वैश्विक अंतर-संचालन की सुविधा मिले। आज रणनीतिक स्वायत्तता 'समाप्ति का निर्णय' अपने हाथ में सुनिश्चित करते हुए वैश्विक नेटवर्क में भाग लेने की क्षमता है।

संघर्ष समाप्ति का अनुशासन : संघर्ष समाप्ति रणनीतिक समझ की सबसे स्पष्ट कसौटी है। कार्रवाई करते हुए यह जानना जरूरी है कि रुकना कब है। 1971 का संघर्ष इस अनुशासन हेतु वैश्विक मानदंड है: एक निर्णायक सैन्य परिणाम पाने के बाद,अपने क्षेत्रीय विस्तार बिना, एक नए राष्ट्र के लिए संप्रभु स्थिरता की तुरंत स्थापना करना। 1947 से आज तक भारत द्वारा बल प्रयोग, अंतर्निहित इस सीमा को ध्यान में रखने का बिम्ब रहा है, इरादे का संकेत देना, दुश्मन को कीमत चुकाने पर मजबूर करना, और उसको संदेश मिलने के बाद पीछे हटने की क्षमता। ऑपरेशन सिंदूर खास किस्म के इस संयम की उत्तम मिसाल है : बेकाबू टकराव की गंभीरता तजे बिना, इतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना जिससे रणनीतिक दिशा बदली जा सके।

नए युग में केंद्र बिंदु की भूमिका : यांत्रिक दृष्टि से, 'केंद्र बिंदु' बनने का मतलब व्यवस्था पर हावी होना नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन बनाने में मदद करना है। इसकी अहमियत ताकत में नहीं, स्थिरता में है जो दूसरों को हासिल करने में मदद करे। ऐसी भूमिका निभाने में जिम्मेवारी सिर्फ़ स्थिरता रखना ही नहीं, सही संकेत देने की भी होती है। सार्वजनिक तौर पर चुप रहने का अर्थ ज़रूरी नहीं निष्क्रियता हो, खुले तौर पर संयम और पर्दे के पीछे खास मकसद के काम साथ चल सकते हैं। भारत नई द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था में एक ध्रुव बनने की चाहत नहीं रखता। लेकिन जहां विभिन्न ताकतें परस्पर उलझी हों, वहां विकल्पों को स्पष्ट कर सकता है और ऐसे नतीजों को मज़बूती दे सकता है जिनसे संतुलन बहाल हो सके।

निष्कर्ष : संतुलन चुनना : जो देश अपने घर के अंदर खुद को स्थिर रख पाते हैं, वे बाहरी व्यवस्था को स्थिर रखने में ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। भारत का विशाल आकार उसे ये दोनों काम करने की सुविधा देता है- अपने महाद्वीपीय स्वरूपके साथ समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता का परिदृश्य बनाना। ऐसा करके, सिर्फ़ लहरों संग बहने के बजाय, उस ज़मीन को ही आकार देना है जिससे जाकर वे लहरें आकर टकराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भले ही कमज़ोर हो रही हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। इस संधि-काल में लिए फ़ैसले ही तय करेंगे कि भविष्य बिखराव की ओर जाएगा या संतुलन की ओर। भारत का रास्ता न तो टकराव वाला है और न ही पूरे समर्पण वाला। यह संतुलन को आदर्श के बजाय बतौर जरूरत देखना चाहता है। भारत वैश्विक साझेदारी की भाईचारे की प्रकृति और सबकी भलाई की खातिर उसे सहेजकर रखने की जरूरत को मानता है। अगर दुनिया का छोटा सा हिस्सा भी ध्रुवीकरण की बजाय संतुलन चुन ले, तो वाजिब संतुलन अभी भी कायम हो सकता है। भारत को दुनिया में अपनी जगह ढूंढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत अपने-आप में एक जगह है।

प्रेरणा

स्वतंत्रता का मूल्य: जब एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति से ऊपर राष्ट्र को चुना

इतिहास केवल युद्धों, तिथियों और विजयों का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह उन महान निर्णयों की कहानी भी होता है, जो किसी राष्ट्र की आत्मा को आकार देते हैं। जब-जब किसी देश के सामने संकट आया है, तब-तब कुछ ऐसे व्यक्तित्व सामने आए हैं, जिन्होंने अपने निजी हितों को त्यागकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी एक घटना इसी त्याग, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

यह प्रसंग उस समय का है जब American Revolutionary War अपने निर्णायक दौर में था। ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संघर्ष चरम पर था। Boston उस समय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बन चुका था, जिस पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था। शहर के भीतर ब्रिटिश सैनिक सुरक्षित थे, लेकिन बाहर से अमेरिकी सेनाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। इस घेराबंदी के कारण ब्रिटिश सेना को आवश्यक रसद और आपूर्ति मिलने में भारी कठिनाई हो रही थी।

अमेरिकी सेना के नेतृत्व में खड़े George Washington ने इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि यदि कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया, तो यह युद्ध लंबा खिंच सकता है और परिणाम अनिश्चित हो सकता है। इसलिए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक साहसिक प्रस्ताव रखा—बोस्टन नगर पर बमबारी की जाए, ताकि ब्रिटिश सेना को वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा सके।

यह प्रस्ताव जितना रणनीतिक रूप से प्रभावी था, उतना ही भावनात्मक रूप से कठिन भी। कांग्रेस के सभी सदस्य इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गए कि क्या अपने ही एक प्रमुख नगर को नष्ट करना उचित होगा। बोस्टन केवल एक युद्धस्थल नहीं था, बल्कि हजारों लोगों के जीवन, उनकी आशाओं और उनकी संपत्तियों का केंद्र था। बमबारी का अर्थ था—अपने ही नागरिकों को भारी नुकसान पहुँचाना।

इस कठिन परिस्थिति में सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति थे कांग्रेस के अध्यक्ष John Hancock। उनकी अधिकांश संपत्ति बोस्टन में ही स्थित थी। यदि बमबारी का निर्णय लिया जाता, तो उनका सब कुछ नष्ट हो सकता था। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि उनके जीवनभर की मेहनत और उपलब्धियों का विनाश था। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करता।

लेकिन यही वह क्षण था, जिसने जॉन हैनकॉक को एक साधारण व्यक्ति से असाधारण नेता बना दिया। उन्होंने परिस्थिति को समझा और यह महसूस किया कि उनकी व्यक्तिगत स्थिति के कारण अन्य सदस्य निर्णय लेने में झिझक रहे हैं। यदि यह दुविधा बनी रहती, तो यह राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो सकती थी।

उन्होंने तुरंत खड़े होकर सदन को संबोधित किया। उनके शब्दों में न केवल स्पष्टता थी, बल्कि एक गहरी देशभक्ति भी झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि उनकी पूरी संपत्ति बोस्टन में है और बमबारी से वह नष्ट हो सकती है। लेकिन यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है, तो इस निर्णय में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी संपत्ति के नष्ट होने का कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व होगा कि उनका निजी नुकसान देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान बन सका। उनके इस त्यागपूर्ण वक्तव्य ने कांग्रेस के अन्य सदस्यों को गहराई से प्रभावित किया और उनकी दुविधा समाप्त हो गई।

यह घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कठिन निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सोचता है, तभी वह सच्चा देशभक्त बनता है।

आज के समय में, जब अधिकांश लोग व्यक्तिगत लाभ और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं, यह प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी ऐसे निर्णय लेने का साहस रखते हैं, जहाँ हमें अपने हितों का त्याग करना पड़े? क्या हम अपने समाज और देश के लिए उतने ही समर्पित हैं, जितने उस समय के लोग थे?

राष्ट्र के प्रति कर्तव्य केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन निभाया जाता है। जब हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जब हम नियमों का पालन करते हैं, जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं—तब हम अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है, तब वही लोग आगे आते हैं, जिनके भीतर पहले से ही त्याग और समर्पण की भावना होती है।

इस प्रसंग का एक महत्वपूर्ण पहलू नेतृत्व का भी है। एक सच्चा नेता वही होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का साहस रखता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचता है। जॉन हैनकॉक ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व का अर्थ केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना होता है।

उनका यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। यह हमें यह समझाता है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके नागरिकों के चरित्र में होती है। जब लोग अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तब वह देश अजेय बन जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसे बनाए रखने के लिए हमें समय-समय पर अपने निजी हितों का त्याग करना पड़ता है। जॉन हैनकॉक का यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि जब राष्ट्र पुकारे, तो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहिए। यही सच्चा राष्ट्रधर्म है, यही कर्तव्य है, और यही वह भावना है, जो किसी भी देश को महान बनाती है।

राम भाव में ही है मनुष्यता का भविष्य

शाश्वत मूल्य बोध के विग्रह स्वरूप श्रीराम भारतीय संस्कृति के एक ऐसे लोक-विश्रुत मानवीय उत्कर्ष हैं जो पढ़े-लिखे और अनपढ़ समाज के हर वर्ग के लिए युगों-युगों से प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। साहित्य जगत ने राम-कथा में कल्पना और रस का अजस्र स्रोत ढूंढ़ा है और अनगिनत कवियों और लेखकों ने अपने सृजन का आधार बनाया। साहित्य की इस परंपरा का स्पष्ट संदेश है कि पृथ्वी पर श्रीराम का आविर्भाव और अवतरण मात्र लोक कल्याण के हित हुआ। उन्हें अयोध्या के राजा के पुत्र दशरथनंदन के व्याज से मानुष भाव में प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय मनीषा मनुष्यता की चुनौतियों, उसके द्वंद्वों, संघर्षों और उपलब्धियों से परिचित कराते हैं।

वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। उसमें वर्णित श्रीराम की विलक्षण गाथा मनुष्य द्वारा सत्य के चरम साक्षात्कार करते रहने के लिए निर्मम आह्वान करती है। यह अलौकिक गाथा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कदाचित मनुष्य जीवन की यह एक अनिवार्य विडंबना है कि उसमें ऊपर उठने और नीचे गिरने, दोनों तरह की प्रवृत्तियां सहज संभव हैं। जीवन में दिन और रात की तरह उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों की उपस्थिति स्वाभाविक है। इनके बीच संतरण के लिए धर्म के अनुकूल कर्तव्य पालन ही एकमात्र साधन उपलब्ध है। यही वह रसायन या प्रौद्योगिकी है, जो जीवन में अनुभव की जाने वाली सीमाओं को संभावनाओं में बदल देती है।

श्रीराम का पूरा जीवन ही विभिन्न भूमिकाओं के आपसी द्वंद्वों और उससे जुड़ी तरह-तरह की चिंताओं से भरा हुआ है। पुत्र, शिष्य, पति, भाई, युवा, मित्र, योद्धा और राजा आदि विभिन्न रूपों में श्रीराम लगातार एक से बढ़कर एक चुनौती का सामना करते हैं। उन्हें लगातार पीड़ा सहनी पड़ती है और दुख उठाने पड़ते हैं। एक प्रतापी राजा के युवराज होने पर भी उनके धैर्य की परीक्षा कदम-कदम पर जीवन भर निरंतर ली जाती रही। लंकापति रावण के रूप में उनके सम्मुख चरम जटिलता वाली चुनौती उपस्थित होती है। ज्ञानी और समृद्ध राजा होकर भी धर्म का विरोध करने की दुर्बुद्धि रावण को श्रीराम का शत्रु बना देती है। वह शौर्य में अद्वितीय था, फिर भी उसे धर्मविरुद्ध आचरण करने में किसी तरह की शंका नहीं होती। परिणामस्वरूप उसकी स्वर्णपुरी विनष्ट हो गई।

जीवन में आने वाले संघर्षों के समाधान के लिए श्रीराम एक नीतिज्ञ के रूप में अपनी दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह की शक्तियों को संयोजित करते हैं। वे नर हों या वानर, सबका सहयोग लेते हैं और धर्म की रक्षा करने का जतन करते हैं। वे स्वयं मर्यादा का निर्वाह करते हैं और उसके उल्लंघन को दंडित करना उनकी नीति है। श्रीराम के धर्म की गत्यात्मकता ही उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। तभी भारत के साथ कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में श्रीराम लोकप्रिय हुए। वे जन-स्मृति का हिस्सा बनते गए और उनकी कथा सबके मानस में गहरे उतरती गई।

इसका प्रमाण है अनेकानेक भाषाओं में राम-कथा का निरंतर लेखन, अंकन, मंचन और गायन। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के लोकार्पण के बाद कुछ ही समय में करोड़ों भक्तों के आगमन और उनके दर्शन-लाभ लेने से श्रीराम की भारतीय मानस में उकेरी दिव्य छवि की पुष्टि हुई है। रामायण आज भारत की हर भाषा में है और सबने हृदय से उसे अपनाया, पर उसे आत्मसात करते हुए क्षेत्र विशेष की परंपराओं के अनुसार राम कथा के कथानक और आख्यानों में भी बदलाव आया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम अपने हैं और अपना अपनों जैसा ही होना चाहिए। अवधी में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी का 'रामचरितमानस' पिछली पांच सदियों से लोक जीवन में प्रतिष्ठित है।

आज के परिवेश में श्रीराम का स्मरण हमें अपने स्वभाव और कर्म पर विचार करने को उद्यत करता है। आज विश्व में युद्ध, आतंक और हिंसा की तीव्र और ऊंची लहरें सतत उठ रही हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के तात्कालिक कारण अक्सर बदले की भावना और उससे उपजती फौरी कारवाई होती है, परंतु अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और लिप्सा सबको लीलती जा रही है। अनियंत्रित लोभ इनके लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाते हैं। इसके पीछे आज की बदलती जीवन दृष्टि ही जिम्मेदार प्रतीत होती है। धर्म और अधर्म से परे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने और बढ़ाते रहना ही आज के विश्व में प्रिय हो रहा है, पर इसके दुष्परिणाम सर्वत्र दिख रहे हैं। मनुष्य जीवन तो दूभर हो ही रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रदूषित और क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक युद्ध चार वर्षों से चल रहा है। एक दूसरा जारी है, जो सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आज धरती पर जीवन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बड़े, धनी और राजनीतिक प्रभाव वाले देश नियमों, कानूनों और मानवीय मूल्यों को धता बताते हुए दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए अपने को स्वतंत्र समझते हैं। निराशाजनक यह कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन निष्प्रभावी दिख रहे हैं।

संसार में धर्म ही सार है। श्रीराम का धर्म-भाव आदर्श, मर्यादा, धैर्य, सहनशीलता, त्याग, समानता, प्रेम, विनम्रता और क्षमा के आचरण में प्रकट होता है। इस राम भाव को आत्मसात करने में ही मनुष्यता का भविष्य छिपा है। आइए हम सब इसके माध्यम बनें।

अभियान

जाखू पर्वत का अद्भुत रहस्य: जहां आज भी गूंजती है हनुमान के चरणों की आस्था

देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी अलौकिक सुंदरता, शांत वातावरण और चमत्कारी धार्मिक स्थलों के लिए पूरे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां की हर घाटी, हर पर्वत और हर मंदिर किसी न किसी दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्थान है Jakhu Temple, जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि पौराणिक रहस्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

यह मंदिर Shimla की सबसे ऊंची चोटी जाखू हिल पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,438 मीटर मानी जाती है। चारों ओर घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। यहां स्थापित भगवान Hanuman की विशाल प्रतिमा दूर-दूर से दिखाई देती है और श्रद्धालुओं के मन में अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न करती है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों में से एक मानी जाती है, जो इस मंदिर की पहचान बन चुकी है।

जाखू मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक और रहस्यमयी मान्यता यह है कि यहां आज भी हनुमान जी के चरणचिह्न मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये पदचिन्ह उस समय के हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे। इस कथा का संबंध सीधे Ramayana से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और आस्था का आधार स्तंभ है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब लंका में युद्ध के दौरान Lakshmana मेघनाथ के शक्तिबाण से मूर्छित हो गए थे, तब उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जो केवल हिमालय में पाई जाती थी। ऐसे संकटपूर्ण समय में भगवान राम ने हनुमान जी को संजीवनी लाने का आदेश दिया। हनुमान जी बिना विलंब किए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर निकल पड़े।

इसी यात्रा के दौरान उनकी दृष्टि जाखू पर्वत पर पड़ी। उस समय यह स्थान अत्यंत पवित्र और तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध था, जहां एक यक्ष ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। हनुमान जी ने सोचा कि यहां उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में सही जानकारी मिल सकती है, इसलिए वे इस पर्वत पर उतरे। मान्यता है कि जब उन्होंने इस पर्वत पर कदम रखा, तो उनके दिव्य भार के कारण यह पहाड़ी थोड़ी धंस गई, जिसके कारण आज भी जाखू हिल ऊपर से कुछ चपटी दिखाई देती है।

हनुमान जी ने यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की और थोड़ी देर विश्राम भी किया। उस समय ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि लौटते समय उन्हें दर्शन अवश्य दें। हनुमान जी ने यह वचन स्वीकार कर लिया और फिर तुरंत अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए।

जब हनुमान जी संजीवनी लेकर वापस लौट रहे थे, तब उनका सामना कालनेमि नामक राक्षस से हुआ। कालनेमि ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे हनुमान जी को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई और वे सीधे लंका की ओर बढ़ गए। इस कारण वे यक्ष ऋषि को दिए गए वचन के अनुसार तुरंत दर्शन नहीं दे पाए।

यक्ष ऋषि इस बात से व्याकुल हो गए और उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी पुनः जाखू पर्वत पर प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। उसी समय वहां हनुमान जी की एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे ऋषि ने अत्यंत श्रद्धा के साथ स्थापित किया। यही स्थान आगे चलकर जाखू मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

कहा जाता है कि उस समय हनुमान जी के चरणों के निशान इस पर्वत पर अंकित हो गए थे, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। श्रद्धालु इन पदचिन्हों के दर्शन करते हैं और उन्हें पूजते हैं। लोगों का विश्वास है कि इन चरणचिह्नों में अद्भुत दिव्य शक्ति है और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर मनोकामना पूरी होती है।

जाखू मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और पौराणिक इतिहास का जीवंत प्रमाण भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को भी महसूस करते हैं, जो इस स्थान को विशेष बनाती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है।

इस मंदिर की एक और विशेषता यहां के बंदर हैं, जिन्हें हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। ये बंदर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और श्रद्धालुओं के साथ एक अलग ही संबंध बनाते हैं। हालांकि, यहां आने वाले लोगों को सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये बंदर कभी-कभी शरारती भी हो सकते हैं।

जाखू मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। यहां से शिमला शहर का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है, जब पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है।

आज के आधुनिक युग में भी जाखू मंदिर की महत्ता और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमें हमारी पौराणिक जड़ों और सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है।

इस मंदिर से जुड़ी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। यक्ष ऋषि की भक्ति ने हनुमान जी को पुनः प्रकट होने के लिए प्रेरित किया, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं।

अंततः जाखू मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है—एक ऐसा अनुभव, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यहां के पदचिन्ह केवल पत्थरों पर बने निशान नहीं हैं, बल्कि वे उस दिव्य स्पर्श के प्रतीक हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में विश्वास और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात का 'बनास BIO-CNG' मॉडल बन रहा कचरे से कंचन और ग्रामीण समृद्धि का नया राष्ट्रीय मानक

- BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य बजट में किया 60 करोड़ का प्रावधान
- BIO-CNG गैस और जैविक उर्वरक की बिक्री से प्रति संयंत्र सालाना लगभग 12 करोड़ राजस्व सृजन का अनुमान
- परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, 'ग्रीन गुजरात' के संकल्प को मिलेगा बल

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के विजन को धरातल पर उतारते हुए गुजरात का विकास मॉडल अब एक सफल राष्ट्रीय मिसाल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में विकसित बनास BIO-CNG प्लांट मॉडल को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और केंद्रीय सहकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों से देश के लगभग 15 राज्य अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बनास डेयरी द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट गोबर जैसे पारंपरिक अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन और जैविक उर्वरक में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रहा है।

BIO-CNG क्षेत्र को गुजरात सरकार का बजटीय समर्थन, 60 करोड़ का आवंटन

गुजरात सरकार ने इस अभिनव पहल की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए BIO-CNG क्षेत्र को अपनी बजटीय प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों द्वारा नए प्लांट स्थापित करने के लिए 60 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। इस बजटीय सहायता का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत राज्य में चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 BIO-CNG प्लांट स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है।

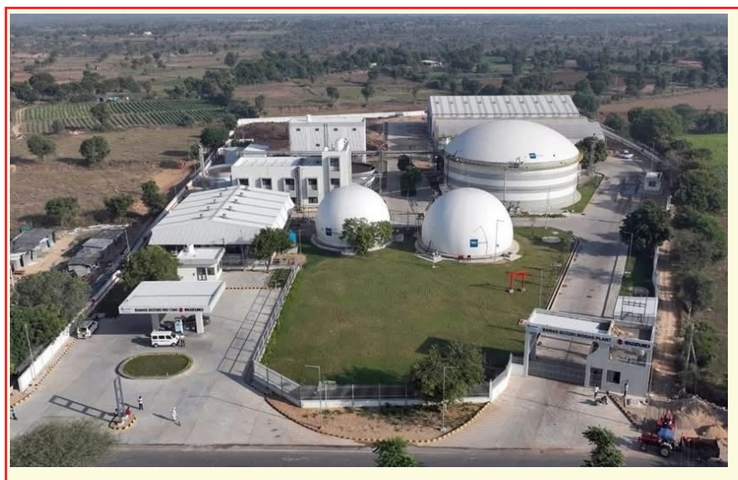

पशुपालक किसानों के लिए BIO-CNG प्लांट बन रहा अतिरिक्त आय का स्रोत

बनासकांठा में स्थापित BIO-CNG संयंत्रों के दायरे में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास स्थित 20-25 गांवों के पशुपालक परिवार जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से गोबर की आपूर्ति करते हैं। किसानों को गोबर के बदले 1 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिससे अनुमानित 400-450 पशुपालक परिवारों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। गोबर संग्रहण और परिवहन के लिए लगभग 13 ट्रैक्टर-ट्रॉली उपयोग में लाई जा रही है, जो लगभग 4-4 मीट्रिक टन प्रति ट्रिप क्षमता के साथ गोबर को संयंत्र तक पहुंचाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

इतना ही नहीं, यह संयंत्र बहु-उत्पाद आधारित आर्थिक मॉडल पर कार्य करता है, जिसके तहत प्रतिदिन लगभग 1,800 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस (CNG) का उत्पादन होता है, जिसे करीब 75 प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही लगभग 25 मीट्रिक टन ठोस जैविक उर्वरक और 75 मीट्रिक टन तरल जैविक उर्वरक का उत्पादन भी होता है, जिन्हें क्रमशः लगभग 6 प्रति किलोग्राम और 0.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इन तीनों उत्पादों से संयंत्र को प्रतिदिन लगभग 3 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है, जो वार्षिक रूप से करीब 12 करोड़ तक पहुंच सकता है।

किसान, उद्योग और पर्यावरण का 'विन-विन' कॉम्बिनेशन है बनास BIO-CNG प्लांट मॉडल

बनासकांठा में 40 मीट्रिक टन प्रतिदिन गोबर प्रसंस्करण क्षमता वाला बनास BIO-CNG प्लांट पिछले 6 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित एक प्रूवन मॉडल है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर बनासकांठा में 5 विशाल BIO-CNG प्लांट्स शुरू करने पर काम जारी है। वर्तमान में नियोजित 5 प्लांट्स में से 2 संयंत्रों ने परिचालन शुरू कर दिया है, जबकि तीसरा प्लांट अपने पूर्णता के अंतिम चरण में है। प्रत्येक प्लांट प्रतिदिन लगभग 100 मीट्रिक टन (1 लाख किलो) गोबर को वैज्ञानिक पद्धति से प्रोसेस करता है। लगभग 50-55 करोड़ की निवेश लागत से निर्मित यह संयंत्र आधुनिक तकनीक और इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि कैसे ईकोलॉजी और ईकोनॉमी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और कैसे पर्यावरण संरक्षण, किसानों की समृद्धि और औद्योगिक प्रगति तीनों एक साथ संभव है।

BIO-CNG प्लान्ट्स से राज्य सरकार के 'ग्रीन गुजरात' के संकल्प को मिल रहा बल

गुजरात की यह अभिनव परियोजना न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। यह मॉडल प्रतिवर्ष लगभग 6,750 टन CO_2e (कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखता है, जो जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती के खिलाफ गुजरात की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। स्वच्छ ईंधन का उत्पादन, रसायनों से मुक्त जैविक उर्वरक की उपलब्धता और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का यह त्रिकोणीय संगम 'ग्रीन बनासकांठा' से होते हुए 'ग्रीन गुजरात' के व्यापक संकल्प को हकीकत में बदल रहा है।

उत्तर गुजरात के विकास का नया अध्याय: बेचराजी रणुज रेलखंड तैयार,सीआरएस निरीक्षण प्रस्ताव अग्रेषित

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2025 को गुजरात दौरे के दौरान 1,400 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसमें बेचराजी–रणुज रेल खंड भी शामिल था, जिसका ब्रॉडगेज में परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 40 किलोमीटर लंबाई एवं 520 करोड़ की लागत से सम्पन्न इस परियोजना के माध्यम से उत्तर गुजरात को सुदृढ़ रेल संपर्क प्रदान किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षित, तेज एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।

बेचराजी–रणुज रेल खंड के अंतर्गत मध्यवर्ती प्रमुख स्टेशनों में खांभेल एवं चाणसमा शामिल हैं, जो महेसाणा एवं पाटण जिलों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में परिवर्तन पूर्ण हो चुका है तथा यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने पर इन क्षेत्रों के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी इलाकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों तथा छोटे व्यापारियों के लिए आवागमन अधिक सुगम, तेज एवं किफायती हो जाएगा।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से बेचराजी मंदिर एवं वहां आयोजित मेला में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु इस रेल सुविधा से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।

यह परियोजना क्षेत्र के कृषि एवं लघु उद्योगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। किसानों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। साथ ही, यह रेल खंड क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि में सहायक होगा। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना एवं राज्य की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार लाना है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि इस खंड पर अब तक मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा था। अब यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने के उद्देश्य से बेचराजी–रणुज रेल खंड का ब्रॉडगेज कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है तथा सीआरएस (Commissioner of Railway Safety) निरीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस खंड पर यात्री रेल सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध यात्रा सुविधा प्राप्त होगी।

इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में Director G-RIDE श्री राजकुमार, जीएम (सिविल) श्री शिवेन्द्र कुमार, अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) श्रीमती मंजू मीणा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. जेनिया गुप्ता तथा वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री वैभव सकलेचा उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान महेसाणा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री हरिभाई पटेल के साथ दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्हें बेचराजी–रणुज रेल खंड के सीआरएस निरीक्षण हेतु प्रेषित प्रस्ताव, वर्तमान प्रगति एवं आगामी यात्री सेवाओं के संचालन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही, इस रेल खंड के विद्युतीकरण (Electrification) के लिए भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई, जिससे भविष्य में इस मार्ग पर और अधिक तेज, पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष रेल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इस परियोजना को उच्च गुणवत्ता मानकों एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया गया है। यह पहल भारतीय रेलवे की यात्री-केंद्रित, आधुनिक एवं विकासोन्मुख कार्यप्रणाली को दर्शाती है। इस रेल खंड के प्रारंभ होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी तथा उत्तर गुजरात के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

स्वास्थ्य बीमा में रिकॉर्ड उछाल: 1.2 लाख करोड़ पार प्रीमियम, तेज क्लेम निपटान से बढ़ा भरोसा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र तेजी से विस्तार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस सेक्टर ने लगभग 9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए कुल प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है। यह उपलब्धि न केवल बीमा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लोगों की सोच और प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं।

बीते कुछ वर्षों में महामारी के अनुभव, बढ़ते इलाज के खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं की अनिश्चितताओं ने आम लोगों को बीमा की ओर अधिक आकर्षित किया है। पहले जहां स्वास्थ्य बीमा को एक अतिरिक्त खर्च माना जाता था, वहीं अब इसे आवश्यक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

सरकार और नियामक संस्थाओं की सक्रिय भूमिका ने भी इस क्षेत्र को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Insurance Regulatory and Development Authority of India ने बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए तय की गई नई समय-सीमाएं इस दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो रही हैं।

नए नियमों के तहत अब कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन की प्रक्रिया एक घंटे के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि फाइनल ऑथराइजेशन अधिकतम तीन घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद बीमा मंजूरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिससे इलाज में देरी और मानसिक तनाव दोनों बढ़ जाते थे। लेकिन अब इन सख्त समय-सीमाओं के लागू होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलना आसान हो गया है और अस्पतालों की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित हुई है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई इस वृद्धि के पीछे कई संरचनात्मक कारण भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पॉलिसीधारकों की औसत आयु में वृद्धि, उच्च कवरेज वाली योजनाओं की बढ़ती मांग और चिकित्सा तकनीकों में हो रहे तेजी से विकास ने बीमा लागत को प्रभावित किया है। आधुनिक इलाज, जैसे एडवांस सर्जरी, रोबोटिक ऑपरेशन और विशेष उपचार पद्धतियां महंगी होती जा रही हैं, जिससे बीमा कंपनियों को भी अपने प्रीमियम में समायोजन करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में आए सुधार ने भी इस क्षेत्र में विश्वास को मजबूत किया है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में जहां 85.66 प्रतिशत दावों का निपटान हुआ था, वहीं 2023-24 में यह थोड़ा गिरकर 82.46 प्रतिशत रहा। हालांकि, 2024-25 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह आंकड़ा बढ़कर 87.50 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह सुधार इस बात का संकेत है कि बीमा कंपनियां अब अपने ग्राहकों के दावों को तेजी और पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं।

डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग भी इस परिवर्तन का एक अहम कारण है। बीमा कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर दावों की जांच और निपटान को अधिक सटीक और तेज बना रही हैं। इससे फर्जी दावों पर रोक लगाने में भी मदद मिल रही है, जिससे पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ी है।

हालांकि, इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। Insurance Regulatory and Development Authority of India के 'बीमा भरोसा' पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में सामान्य और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी कुल 1,37,361 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से लगभग 93 प्रतिशत यानी 1,27,755 शिकायतों का निपटारा उसी अवधि में कर दिया गया, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी, यह संख्या यह दर्शाती है कि उपभोक्ताओं को अभी भी कई स्तरों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इन शिकायतों में प्रमुख रूप से क्लेम में देरी, पॉलिसी की शर्तों को लेकर भ्रम, और अस्पतालों व बीमा कंपनियों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। सरकार और नियामक संस्थाएं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके।

स्वास्थ्य बीमा के इस तेजी से बढ़ते दायरे का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव भी है। इससे न केवल लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब अधिक लोग बीमा के दायरे में आते हैं, तो वे समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है और समग्र स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है।

भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र और अधिक विस्तार करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेलीमेडिसिन और पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स जैसी नई तकनीकों के जुड़ने से यह क्षेत्र और भी उपभोक्ता-केंद्रित बन सकता है। साथ ही, सरकार की ओर से आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार भी इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कुल मिलाकर, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में आई यह तेज वृद्धि केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक और स्वास्थ्य ढांचे में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है।

छापेमारी के दौरान बेकाबू भीड़ का हमला: थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी घायल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां देर रात छापेमारी के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में थानाध्यक्ष मनीष कुमार समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया।

यह घटना राघोपुर प्रखंड के करजाईन थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव की है, जहां पुलिस शराब तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी सरोज कुमार मेहता लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। बुधवार देर रात जब पुलिस टीम ने गांव में छापा मारा, तो आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम आरोपी को लेकर वापस लौट रही थी, तभी अचानक हालात बिगड़ गए। आरोपी से जुड़े लोगों और स्थानीय ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया और देखते ही देखते हमला शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

हमले में थानाध्यक्ष मनीष कुमार को भी चोटें आईं, जबकि अन्य चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार, सभी की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त जांच और निगरानी के लिए भेजा गया है।

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल अतिरिक्त बल को मौके पर भेजा गया। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गांव में फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी है और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया जा रहा है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएसपी बीरपुर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्य आरोपी सरोज कुमार मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस का फोकस हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटनास्थल से मिले गोली के खोखे का पुलिस फायरिंग से कोई संबंध नहीं है, जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी न फैले।

दूसरी ओर, इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों की भी अलग राय सामने आई है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना वारंट के गांव में घुसी और कार्रवाई के दौरान मारपीट की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई थी और आरोपी की गिरफ्तारी पूरी तरह वैध थी।

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे के संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव में रहती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती हैं।

देश भर में सुविधाजनक पुलियाएँ (सब वे) बनाने का रेल मंत्री का निर्देश

रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर इन रेल पुलियाओं (सब वे) से लगेगी रोक,पटरी के आर पार इन सुगम पुलियाओं (सब वे) का निर्माण मात्र 12 घंटे में किया जा सकेगा

(जीएनएस)। रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को अब रेलवे मिशन मोड में रोकेगा। सुविधाजनक पुलियाएँ (सब वे) बनाकर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारियों के रूप में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों की एक workshop की।

जहाँ रेल पटरी के एक तरफ बस्ती है और दूसरी तरफ़ खेत, विद्यालय, श्मशान या अन्य उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे स्थानों पर ये रेल पुलियाएँ (सब वे) बनाई जायेंगी। रेल मंत्री ने देशभर में ऐसी रेल पुलियाओं (सब वे) को बनाने का निर्देश दिया, जहाँ अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़ी संख्या में लोग पटरियों को पार करते हैं।

उभरेगी रेल पुलिया (सब वे)

- रेल मंत्री ने अधिकारियों को एक ऐसी सुविधाजनक रेल पुलिया (सब वे) बनाने को कहा जो पटरी पार करने वाले लोगों के लिए एक जीवनदायिनी विकल्प के रूप में उभरे।
- इन रेल पुलियाओं (सब वे) को बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि एक आम आदमी साइकिल, मोटर साइकिल तथा कामकाज से जुड़ी अन्य चीजों को भी अपने साथ ले जा सके। इससे देशभर में पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। देश की एक बड़ी आबादी के लिए भारतीय रेल की ये पुलिया (सब वे) वरदान साबित होगी।

सुगम और सुरक्षित डिज़ाइन

- रेल मंत्री ने अधिकारियों को देश की इस बड़ी समस्या से अगले 5-6 वर्षों में निजात दिलाने को कहा। ये पुलियाएँ (सब वे) इस प्रकार से बनाई जायेंगी ताकि पटरियों के आर पार इनका निर्माण मात्र 12 घंटे में हो सके।
- रेल मंत्री ने कहा कि, डिज़ाइन इस प्रकार की हो, ताकि लोगों को इसे इस्तेमाल करने में कोई हिचक न हो। जल भराव से पुलिया (सब वे) प्रभावित न हो।
- रेल पुलिया (सब वे) बनाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय पिछले कई दिनों से अधिकारियों के साथ चली आ रही मंत्रणा का परिणाम है।
- रेल मंत्री का मानना है कि, व्यवस्था संवेदनशील हो तथा एक आम आदमी की समस्यों का सभी अधिकारी ऐसा समाधान निकालें जो आने वाले कई दशकों तक प्रभावी रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद एवं मंगलुरु के बीच संचालित की जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि को 29 मई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार से यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी तथा अतिरिक्त भीड़ का सुचारु प्रबंधन किया जा सकेगा। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित संरचना, मार्ग, समय एवं रखरखाव व्यवस्था के साथ विशेष किराए पर यथावत संचालित होती रहेगी।

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) [8 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से 16:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे मंगलुरु पहुंचेगी।

प्रमुख ठहराव:

यह ट्रेन नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंन्दापुरा, उडुपि, मुल्की एवं सुरतकल स्टेशनों पर ठहरेगी।

कोच संरचना:

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग जानकारी:

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों एवं IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यात्रीगण से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें।

ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार का कड़ा जवाब "देश में पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर फैल रही कमी की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि देश में किसी भी प्रकार का ईंधन संकट नहीं है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने आधिकारिक बयान जारी कर यह साफ किया कि सभी राज्यों में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पेट्रोल पंपों से लेकर गैस एजेंसियों तक पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैलने लगी थी कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है, जिसके चलते लोगों ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त ईंधन भरवाना शुरू कर दिया। इस तरह की अचानक बढ़ी मांग ने कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव जरूर बनाया, लेकिन सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें, क्योंकि अफवाहें न केवल अनावश्यक घबराहट पैदा करती हैं बल्कि आपूर्ति व्यवस्था पर भी दबाव डालती हैं।

सरकार के अनुसार, देशभर में एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं और कहीं भी राशनिंग लागू नहीं की गई है। न ही किसी पेट्रोल पंप को ईंधन की आपूर्ति सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आम उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन सहज रूप से मिलता रहेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत बताते हुए मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि देश आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवां सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक बन चुका है। भारत 150 से अधिक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है, जो उसकी उत्पादन क्षमता और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर भले ही ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हों, लेकिन भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को काफी विविधतापूर्ण बना लिया है। वर्तमान में देश को 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति मिल रही है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव या संकट की स्थिति में भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित नहीं होती।

देश की रिफाइनरियां भी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। ये रिफाइनरियां न केवल घरेलू मांग को पूरा कर रही हैं, बल्कि निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन स्टॉक मौजूद है, जबकि कुल भंडारण क्षमता 74 दिनों तक की है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक होने का मतलब है कि अचानक मांग बढ़ने या सप्लाई में अस्थायी बाधा आने पर भी आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

एलपीजी आपूर्ति के मोर्चे पर भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक बताई गई है। सरकार के अनुसार, उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है और प्रतिदिन 50 लाख से अधिक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से मिल रही है।

गोबर से गैस, कचरे से कमाई: बनास BIO-CNG मॉडल से 'ग्रीन गुजरात' की नई क्रांति, देश के लिए बना उदाहरण

(जीएनएस)। गांधीनगर/बनासकांठा। प्रधानमंत्री Narendra Modi के 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के विजन को जमीन पर उतारते हुए गुजरात ने एक बार फिर विकास का नया मानक स्थापित किया है। राज्य के बनासकांठा जिले में विकसित बनास BIO-CNG मॉडल आज न केवल 'ग्रीन गुजरात' मिशन को गति दे रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक सफल और व्यावहारिक मॉडल बनकर उभरा है। इस परियोजना की खासियत यह है कि यह पारंपरिक अपशिष्ट यानी गोबर को स्वच्छ ईंधन और जैविक उर्वरक में बदलकर पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही है।

मुख्यमंत्री Bhupendra Patel के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने इस पहल को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए BIO-CNG सेक्टर के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से नए प्लांट स्थापित करने के लिए 60 करोड़ का विशेष बजटीय प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य डेयरी सेक्टर को केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रखकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाना और किसानों की आय के नए स्रोत विकसित करना है।

इस मॉडल की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Ministry of Jal Shakti और Ministry of Cooperation के संयुक्त प्रयासों से देश के करीब 15 राज्य इस मॉडल को अपने यहां लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि गुजरात का यह प्रयोग अब राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले रहा है।

बनास डेयरी द्वारा विकसित यह BIO-CNG प्रोजेक्ट पिछले छह वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और इसे एक 'प्रूवन मॉडल' के रूप में मान्यता मिल चुकी है। बनासकांठा में स्थापित यह संयंत्र प्रतिदिन 40 मीट्रिक टन गोबर के प्रसंस्करण की क्षमता रखता है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर अब जिले में पांच बड़े BIO-CNG प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से दो पहले ही शुरू हो चुके हैं और तीसरा अंतिम चरण में है।

प्रत्येक नए प्लांट की क्षमता लगभग 100 मीट्रिक टन गोबर प्रतिदिन प्रोसेस करने की है। करीब 50 से 55 करोड़ की लागत से तैयार ये संयंत्र आधुनिक तकनीक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन उदाहरण हैं। यह मॉडल यह साबित करता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं, विरोधी नहीं। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पशुपालक किसानों को मिल रहा है। बनासकांठा के करीब 20 से 25 गांवों के लगभग 400 से 450 पशुपालक परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। वे नियमित रूप से गोबर की आपूर्ति करते हैं, जिसके बदले उन्हें 1 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान मिलता है। यह उनके लिए एक अतिरिक्त और स्थिर आय का स्रोत बन गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिल रहा है।

गोबर के संग्रहण और परिवहन के लिए स्थानीय स्तर पर 13 ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग किया जा रहा है, जो हर ट्रिप में लगभग 4 मीट्रिक टन गोबर संयंत्र तक पहुंचाते हैं। इससे न केवल किसानों को आय मिल रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

यह BIO-CNG संयंत्र केवल गैस उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहु-उत्पाद आधारित आर्थिक मॉडल पर काम करता है। प्रतिदिन लगभग 1,800 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस (CNG) का उत्पादन किया जाता है, जिसे लगभग 75 प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में बेचा जाता है। इसके अलावा, 25 मीट्रिक टन ठोस जैविक उर्वरक और 75 मीट्रिक टन तरल जैविक उर्वरक भी तैयार किए जाते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है।

इन सभी उत्पादों से संयंत्र को प्रतिदिन करीब 3 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है, जो सालाना लगभग 12 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस तरह यह मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह व्यवहारिक और लाभदायक साबित हो रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी इस परियोजना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मॉडल हर साल लगभग 6,750 टन CO2e (कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि गुजरात जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

स्वच्छ ईंधन का उत्पादन, रसायन मुक्त जैविक उर्वरकों की उपलब्धता और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन—इन तीनों का समन्वय इस परियोजना को विशेष बनाता है। यह मॉडल 'ग्रीन बनासकांठा' से आगे बढ़कर 'ग्रीन गुजरात' के व्यापक लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मॉडल को देशभर में बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, तो यह न केवल ऊर्जा संकट को कम करने में मदद करेगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

कुल मिलाकर, बनास BIO-CNG मॉडल यह दिखाता है कि सही नीति, तकनीक और सामूहिक प्रयासों के जरिए कैसे एक साधारण संसाधन—जैसे गोबर—को बहुमूल्य संपत्ति में बदला जा सकता है। यह पहल भारत के ग्रामीण विकास, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है।

गुजरात में राम नवमी की भक्ति धूम: शोभा यात्राओं, भजनों और युवाओं की रचनात्मकता से गूंजा 'जय श्री राम'

(जीएनएस)। अहमदाबाद। Ram Navami के पावन अवसर पर गुजरात पूरी तरह भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। राज्य के शहरों से लेकर कस्बों तक 'जय श्री राम' के जयघोष गूंजते रहे और जगह-जगह रंगारंग शोभा यात्राएं, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। पारंपरिक श्रद्धा और आधुनिक रचनात्मकता का अनोखा संगम इस बार के उत्सव की सबसे खास पहचान रहा। भगवान Lord Rama की जयंती के इस पावन दिन पर Ahmedabad, Rajkot, Vadodara और Surat समेत राज्य के कई शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं। इन यात्राओं में सजी-धजी झांकियां, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियां और भक्ति संगीत ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। सड़कों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस पर्व को एक जनउत्सव का रूप दे दिया। अहमदाबाद स्थित ISKCON Temple Ahmedabad में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन

किया गया। सुबह 'श्री राम दरबार अभिषेक' के साथ भगवान का विधिवत पूजन किया गया और पारंपरिक '56 भोग' अर्पित किया गया। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। शाम के समय भव्य पालकी यात्रा निकाली गई और राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को श्रद्धापूर्वक सुना।

राजकोट और वडोदरा में निकली शोभा यात्राओं ने भी लोगों का मन मोह लिया। इन यात्राओं में धार्मिक झांकियों के माध्यम से रामायण के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कहीं राम-सीता-लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकार दिखाई दिए, तो कहीं हनुमान जी की भव्य झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ढोल-नगाड़ों की गूंज और भजन-कीर्तन की धुनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

इस बार के उत्सव में युवाओं की भागीदारी और रचनात्मकता विशेष रूप से देखने को मिली। परंपरागत आयोजनों के साथ-साथ नए और अभिनव तरीकों से भी राम नवमी का उत्सव मनाया गया। अहमदाबाद के पास अडालज क्षेत्र में शाम के समय भजन-कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया, जहां एक लाइव फ्यूजन बैंड ने पारंपरिक भक्ति संगीत को आधुनिक धुनों के साथ प्रस्तुत किया। इस प्रयोग ने खासकर युवा पीढ़ी को आकर्षित किया और भक्ति को एक नया, समकालीन रूप दिया।

उधर, सूरत में युवाओं के एक समूह ने अनोखे अंदाज में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। करीब 90 बाइकर्स ने डाभरी बीच पर एकत्र होकर अपनी 65 मोटरसाइकिलों को इस तरह व्यवस्थित किया कि ऊपर से देखने पर 'राम' शब्द का आकार दिखाई दे। यह दृश्य न केवल आकर्षण का केंद्र बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। इस पहल के पीछे समूह के संस्थापक पिनांक मशरूवाला का कहना था कि हर राम भक्त का अपने आराध्य के प्रति प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग शोभा यात्राओं, भंडारों और आरती के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी पसंदीदा बाइकों के जरिए भगवान राम के नाम को एक अनोखे रूप में प्रस्तुत किया। गुजरात में इस बार राम नवमी का उत्सव केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक बना। विभिन्न समुदायों के लोगों ने मिलकर इस पर्व को मनाया, जिससे भाईचारे और सामूहिकता की भावना को भी बल मिला।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे पर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। यह न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि लोगों के बीच आपसी संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाते हैं। गुजरात में जिस तरह से पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का संतुलन देखने को मिला, वह इस बात का संकेत है कि भारतीय संस्कृति समय के साथ बदलते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है।

कुल मिलाकर, गुजरात में मनाई गई राम नवमी ने यह संदेश दिया कि आस्था और उत्सव का स्वरूप चाहे बदल जाए, लेकिन उसकी आत्मा वही रहती है। रंगारंग शोभा यात्राएं, भक्ति संगीत, मंदिरों में विशेष पूजा और युवाओं की रचनात्मक पहल—इन सभी ने मिलकर इस पर्व को यादगार बना दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी लोगों को एकजुट करने वाला साबित हुआ।

सूरत में कचरा पहाड़ बना आफत: खाजोद डंपिंग साइट की आग तीसरे दिन भी बेकाबू, 20 लाख लीटर पानी भी पड़ा कम

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के औद्योगिक शहर Surat में स्थित खाजोद डंपिंग साइट पर लगी भीषण आग ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को चुनौती दे दी है। आग लगातार तीसरे दिन भी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है, जबकि फायर विभाग द्वारा अब तक करीब 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव किया जा चुका है। इसके बावजूद कई हिस्सों में धधकती आग, उठता घना धुआं और बार-बार भड़कती लपटें हालात की गंभीरता को साफ तौर पर दिखा रही हैं।

यह आग 24 मार्च की दोपहर अचानक भड़क उठी थी और कुछ ही घंटों में इसने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते कचरे का विशाल पहाड़ आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हवा में जहरीली गंध फैल गई, जिससे सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं महसूस होने लगीं।

फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डंपिंग साइट पर लगी आग को बुझाना सामान्य आग से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। कचरे के ढेर में प्लास्टिक, रबर, केमिकल और जैविक पदार्थों की मौजूदगी के कारण आग भीतर-भीतर सुलगती रहती है, जिसे पूरी तरह बुझाने में काफी समय लगता है। यही वजह है कि लगातार पानी डालने के बावजूद आग बार-बार सुलग उठती है और धुआं निकलता रहता है।

बीते दो दिनों से फायर ब्रिगेड की टीमें दिन-रात मौके पर डटी हुई हैं। 25 मार्च की पूरी रात भी टीमों ने लगातार पानी का छिड़काव किया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। जिन इलाकों से अब भी धुआं उठ रहा है, वहां विशेष रूप से 'कूलिंग ऑपरेशन' चलाया जा रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने और साइट को सुरक्षित घोषित करने में अभी कम से कम दो दिन और लग सकते हैं।

इस घटना ने शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाजोद डंपिंग साइट पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक कचरा जमा होने और उचित प्रबंधन के अभाव को लेकर चर्चा में रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कचरे के ढेर में समय-समय पर गैस बनने और अत्यधिक तापमान के कारण स्वतः आग लगने की घटनाएं आम हैं, लेकिन यदि प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि डंपिंग साइट से उठने वाला धुआं उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। कई लोगों ने सिरदर्द, सांस की तकलीफ और एलर्जी की शिकायत की है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और डंपिंग साइट के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की आग से निकलने वाला धुआं बेहद जहरीला होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और अन्य हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ये गैसें न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। लंबे समय तक इस तरह का प्रदूषण रहने से वायु गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। प्रशासन फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाने, आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखने और लोगों को राहत पहुंचाने पर है।

होली की रात दोस्त बना कातिल: शिमला हत्याकांड का खुलासा, बिहार से मुख्य आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में होली की रात हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। Shimla के सुन्नी क्षेत्र में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था, जब एक युवक के लापता होने के बाद उसका शव कई दिनों बाद खेत में गड्ढा खोदकर दबा हुआ मिला। अब पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ के बाद इस खौफनाक साजिश की परतें खुलने लगी हैं।

पुलिस के मुताबिक, बिहार के Muzaffarpur क्षेत्र से आरोपी अरुण कुमार (31) को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से East Champaran का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त राम प्रवेश राम की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में दफना दिया।

इस मामले की पुष्टि करते हुए शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है।

घटना की शुरुआत 15 मार्च को हुई, जब मृतक के पिता ने अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा राम प्रवेश राम शिमला के बसंतपुर क्षेत्र में अपने साथियों के साथ निर्माण कार्य कर रहा था और 3-4 मार्च की रात से अचानक लापता हो गया। शुरू में इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला माना गया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता बढ़ती गई और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया।

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। इन्हीं के आधार पर पुलिस को यह सुराग मिला कि मृतक का अपने साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यही विवाद बाद में उसकी हत्या की वजह बना। तकनीकी जांच ने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई।

लगातार जांच और सर्च ऑपरेशन के बाद 23 मार्च को पुलिस ने घटनास्थल के पास एक खेत में खुदाई कर शव बरामद किया। शव को गड्ढा खोदकर दबाया गया था, जिससे साफ था कि आरोपी ने अपराध को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। शव की पहचान राम प्रवेश राम के रूप में होते ही मामले ने और गंभीर रूप ले लिया।

इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की, जिसने विभिन्न राज्यों में दबिश देना शुरू किया। आखिरकार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद अब मामले की कड़ियां तेजी से जुड़ रही हैं और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा।

यह मामला न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि यह विश्वास और दोस्ती के टूटने की एक दर्दनाक कहानी भी है। जिस व्यक्ति के साथ मृतक काम करता था और जिस पर भरोसा करता था, उसी ने कथित तौर पर उसकी जान ले ली। इस घटना ने समाज में रिश्तों और भरोसे को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे केवल आपसी विवाद था या कोई और गहरी वजह भी थी।

बिना टिकट यात्रा पर सख्ती: वडोदरा मंडल ने टिकट जांच अभियान से कमाए 18 करोड़ रुपये

(जीएनएस)। वडोदरा। Western Railway के Vadodara Division ने सघन टिकट जांच अभियान के जरिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 मार्च 2026 तक 18 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल रेलवे की सख्ती और सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि यात्रियों के बीच नियमों के पालन के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी संकेत देती है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वडोदरा मंडल लगातार बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर टिकट जांच अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वैध यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी यात्रा सुविधा प्रदान करना है,

ताकि नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सफलता के पीछे नियमित और सघन टिकट जांच, क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ पर्यवेक्षण, मजबूत सतर्कता तंत्र और यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का अहम योगदान रहा है। टिकट जांच टीम ने विभिन्न ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

इस दौरान न केवल बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया, बल्कि अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी नियमों के तहत दंडित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाई से रेलवे को आर्थिक मजबूती मिलती है, साथ ही यात्रियों के बीच अनुशासन और नियमों के पालन की भावना भी विकसित होती है।

वडोदरा मंडल की टिकट जांच टीम के समन्वित प्रयास, प्रभावी निगरानी और कार्यकुशलता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीम ने विभिन्न स्तरों पर रणनीति बनाकर अभियान को सफल बनाया, जिसमें अचानक जांच, विशेष ड्राइव और संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी शामिल रही।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि ऐसे अभियान केवल राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह पूरे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में भी मदद करते हैं। जब यात्री नियमों का पालन करते हैं, तो ट्रेनों में भीड़ नियंत्रण, सीट प्रबंधन और यात्रा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वडोदरा मंडल आगे भी इसी तरह के सघन टिकट जांच अभियान जारी रखेगा। साथ ही, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने और रेलवे सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।

सोना वायदा 3175 रुपये और चांदी वायदा 14090 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 427 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118480.18 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 7765.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 110714.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 798.24 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 6043.69 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 139800 रुपये के भाव पर खूलकर, 141433 रुपये के दिन के उच्च और 139800 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 144097 रुपये के पिछले बंद के सामने 3175 रुपये या 2.2 फीसदी लुढ़ककर 140922 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 2450 रुपये या 2.12 फीसदी घटकर 113217 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 294 रुपये या 2.03 फीसदी घटकर 14171 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 144000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 144000 रुपये और नीचे में 140300 रुपये पर पहुंचकर, 3441 रुपये या 2.38 फीसदी घटकर 140897 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 141003 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 141777 रुपये और नीचे में 140400 रुपये पर पहुंचकर, 144036 रुपये के पिछले बंद के सामने 3435 रुपये या 2.38 फीसदी घटकर 140601 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 225441 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 225441 रुपये और नीचे में 220744 रुपये पर पहुंचकर, 234834 रुपये के पिछले बंद के सामने 14090 रुपये या 6 फीसदी औंधकर 220744 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 14135 रुपये या

कमोडिटी वायदाओं में 7765.45 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 110714.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 6043.69 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

5.92 फीसदी गिरकर 224500 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 14226 रुपये या 5.96 फीसदी गिरकर 224650 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 620.76 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 7.1 रुपये या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 1121.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.65 रुपये या 0.53 फीसदी की बढ़त के साथ 310.95 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.9 रुपये या 0.57 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 334.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 1.65 रुपये या 0.85 फीसदी घटकर 191.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 811.26 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8838 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8944 रुपये और नीचे में 8838 रुपये पर पहुंचकर, 427 रुपये या 5.02 फीसदी की तेजी के संग 8926 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 429 रुपये या 5.05 फीसदी की तेजी के संग 8929 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 277.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 279.2 रुपये के दिन के उच्च और 274.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 पैसे या 0.11 फीसदी के सुधार के साथ 277.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 50 पैसे या 0.18 फीसदी चढ़कर 278 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 3476.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 2567.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 431.86 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 127.83 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 1.58 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 59.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 559.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 249.52 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8588 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 56391 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28501 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 367841 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64720 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7085 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18745 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 71038 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17631 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26156 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 223 रुपये की बढ़त के साथ 834.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 65 पैसे के सुधार के साथ 19.7 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 925 रुपये की गिरावट के साथ 3930 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6356.5 रुपये की गिरावट के साथ 261.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.35 रुपये की गिरावट के साथ 16.3 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 53.2 रुपये की गिरावट के साथ 139 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 15 पैसे की नरमी के साथ 17 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 368.5 रुपये की बढ़त के साथ 1781 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 343.5 रुपये की बढ़त के साथ 653 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.31 रुपये की बढ़त के साथ 20.45 रुपये हुआ।